अध्याय 2

अच्छी कार्यप्रणालियां एवं हरित पहल

2.1 अच्छी कार्यप्रणालियां

हमने पाया कि सीआईएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों ने कुछ खदानों/आसपास के स्थानों में काफी पर्यावरण-पुनर्स्थापना के कार्य किए हैं जैसा कि नीचे बताया गया है:

क्र. सं.	अनुषंगियों का नाम	अपनायी गई उत्तम पद्धति	चित्र
1.	एमसीएल	एमसीएल ने दक्षिण बालंडा जो एक बंद खदान है में ग्रीन बेल्ट और पार्क विकसित किया,	
2.	एनसीएल	एनसीएल की निगाही खदानों को बांस के बागानों के साथ पारिस्थितिकी तौर पर बहाल किया गया है।	

3.	डब्ल्यूसीएल	डब्ल्यूसीएल ने पारिस्थिति की रूप से सानेर यूजी बंद खदान को पुन: चालू किया	
4.	सीसीएल	सीसीएल ने वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई, वृक्षारोपण गतिविधियों, नर्सरी विकास, मिश्रित वानिकी विकास, और वर्मित कमपोस्ट यूनिट के विकास के माध्यम से सतत विकास के साथ पर्यावरण संतुलन के लिए एक विशिष्ट खान सुधार पहल का कायाकलप वाटिका विकसित की है।	
5.	बीसीसीएल	बीसीसीएल ने झुनकुनदर बंद ओसी खदान को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक झील में बदल दिया, जिससे भूजल स्तर को रिचार्ज किया जा सके।	

6.	ईसीएल	डालमिया ओसी की बंद खान पानी से भर गई थी और मत्स्य-पालन और जल शोधन संयंत्र शुरू किया गया है।	
7.	एसईसीएल	एसईसीएल ने हसदेव क्षेत्र के राजनगर ओसीपी में एक पुराने परित्यक्त अधिभार डंप को अनन्या वाटिका में बदल दिया, जो एक विदेशी पार्क है।	

2.2 नवीकरणीय ऊर्जा

सौर ऊर्जा पर्यावरण हितैषी है क्योंकि इसमें बिजली या गर्मी बनाते वक्त शून्य उत्सर्जन होता है। भारत सरकार ने जून 2008 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (मिशन) का शुभारंभ किया। इस मिशन ने मार्च 2022 तक 20000 मेगावाट (एमडब्ल्यू) का लक्षित उत्पादन प्राप्त करने के लिए तीन चरण का दृष्टिकोण अपनाया।

इस मिशन ने मार्च 2018 तक लक्षित पीढ़ी के 32 *प्रतिशत* की उपलब्धि की परिकल्पना की है।

सीआईएल चरण बद्ध तरीके से 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के विकास में निवेश का भावी है, यह भारत सरकार द्वारा मिशन के शुभारंभ का परिणाम है। मिशन द्वारा मार्च 2018 तक अनुमानित उपलब्धि के स्तर के आधार पर, सीआईएल के प्रस्ताव ने सालाना

₹ 55.50 करोड़[5] के ऊर्जा शुल्क में बचत की परिकल्पना की है। चूँकि बिजली उत्पादन और बिजली से संबंधित व्यवसाय में इसकी कोई विशेषज्ञता नहीं थी, इसलिए इसने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) की सेवाओं को बनाए रखा और पहले चरण में 250 मेगावाट के विकास के लिए एसईसीआई के साथ समझौता ज्ञापन (अक्टूबर 2014) किया, जिसकी बाद में (नवम्बर 2014) बीओडी द्वारा पुष्टि की गई।

फरवरी 2015 में, सीआईएल ने मार्च 2019 तक 1000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विकासित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। नीमच के सौर पार्क में भूमि के आवंटन और खुले उपयोग पर मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त आश्वासन के आधार पर, एसईसीआई ने दो 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों का अनुमानित लागत ₹ 1300 करोड़ पर (एसईसीएल और एनसीएल प्रत्येक के लिए एक) स्थापना करने के लिए टेंडर जारी किया (नवम्बर 2015)। एसईसीआई ने डीपीआर और काम के पुरस्कार के लिए सिफारिशें भी दी। इसके बाद, एसईसीआई ने पर्याप्त समय बीत जाने के बाद टेंडर को रद्द करने की सलाह दी (दिसम्बर 2016) क्योंकि यह पाया गया कि इन टेंडर की कीमत और सौर ऊर्जा दर में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। अंतत: जारी किए गए टेंडर नवम्बर 2015 में रद्द कर दिए गए। इसके बावजूद एसईसीआई ने अनुरोध किया (दिसम्बर 2015) कि इन संयंत्रों के लिए डीपीआरएस की तैयारी के लिए उनके शुल्क के रूप में ₹ 7.44 करोड़ की राशि है और सीआईएल ने दिसम्बर 2015 में अनुरोध की गई राशि का निपटारा किया। सेवा प्रदान किए बिना एसईसीआई को भुगतान किया गया था।

सीआईएल ने कहा (नवम्बर 2018) कि सौर ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन में वैधानिक अनुमोदन के लिए बाहरी एंजेंसियों के साथ संपर्क करना शामिल था जो इसके नियंत्रण से परे थे। हालांकि, हमने देखा कि मिशन की प्रगति के साथ सीआईएल 1000 मेगावाट के विकास के अपने चरणों की प्रगति को गति देने में विफल रही।

---

[5] {320x1000x24x365/1000000x0.18 लाख केडब्ल्यूएच x ₹ 1.10 प्रति किलोवाट (₹ 4.94/ केडब्ल्यूएच माइनस 3.84/केडब्ल्यूएच}